नियमित किया जाए। मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन किया जाए। किसी रेल कर्मचारी से आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। रेलों का प्रबन्ध स्वायत्त निकाय को सौंपा जाए। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि की जाए। सेवा में सभी रिक्तियों को भरा जाए। क्वार्टरों के निर्माण हेतु अधिक राशि खर्च की जाए।

सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह बिना किसी और अगर मगर के और टालमटोल की नीति को त्याग कर रेल मजदूरी की उक्त मांगों को स्वीकार कर उनके असन्तोष को दूर करे ताकि मजदूर संघर्ष के रास्ते पर जाने को विवश न हों।

(xvli) Exorbitant escalation of rents demanded by Bombay Port Trust.

SHRI RATANSINGH RAJDA (Bombay South) : Bombay Port Trust is the biggest landlord owning 1800 acres of land in the City of Bombay. Several principal commodity markets such as grain, timber, iron, steel, charcoal, coal, tiles, cotton, sand-lime exist on these lands since generations on monthly tenancy or 15 monthly leases, the rent whereof was revised periodically aggregating about ten times the original rent.

Recently, B.P.T. has demanded escalation of rent amounting to 1000 to 1200 per cent. This exorbitant demand has greatly perturbed and jolted the tenants.

It is worth nothing that government or semi-government departments like Food Corporation, Indian Oil, Defence and Bombay Municipal Corporation have refused to accept such excessive increasement of rent.

If this highly exorbitant rent is imposed taking advantage of non-application of the Rent Act, to B.P.T. lands, the entire trade infrastructure, the backbone of commercial activities in Bombay will come to standstill and thousands of people would be thrown out of jobs.

This exorbitant increment of rent to 1000 to 1200 per cent is not only unjust but it is reckless, arbitrary, atrocious and monstrous also unheard of in any civilised society. Central Government must behave as an ideal landlord, if they exploit the helplessness of common man what remedy lies for common citizens. Let us not push the citizens with ther their backs to the wall. It is high time the Central Government reconsider the decision regarding ill-adise dvincrement of rent.

(xvili) Need for development of areas under Machhlishahr Constitueney of Uttar Pradesh.

श्री शिवशरण वर्मा (मछलीशहर) : मान्यवर, मैं आप के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जोनपुर तहसील शाहगंज व मछली शहर के ब्लाक तथा प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के सभी ब्लाक क्षेत्र कभी देवी आपदाओं से वंचित नहीं रहते। इन छात्रों की प्राकृतिक स्थिति भी बड़ी विलक्षण तथा विडम्बनापूर्ण है। अधिकारियों को इन क्षेत्रों की स्थिति की पूर्ण जानकारी है। इसके बावजूद भी ये सभी क्षेत्र आज तक उपेक्षित हैं। इस वर्ष सभी क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में रहे। ओला-पाला तथा सूखे के कारण लगभग 60 प्रतिशत रबी की फसल नष्ट हो चुकी है। खाद्यान के अभाव के कारण गरीब जनता अत्यन्त उत्पीड़ित है। जनता को आवश्यक खाद्यान उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जो गेहूं जनता को वितरित किया जा रहा है वह ठीक नहीं है इससे जनता अनेकानेक बीमारियों से ग्रस्त हो रही है। इस ओर विशेष ध्यान देने की बात है। विगत कई वर्षों के लगातार देवी आपदाओं के कारण इन क्षेत्रों की जनता की हालत अत्यन्त शोचनीय हो गई है। रबी और खरीफ दोनों फसलों के नष्ट हो जाने से जनता की आर्थिक आय का साधन समाप्त हो गया है। ऐसे घोर संकट काल में भी किसानों से सरकारी देय भू-राजस्व, सिचाई राजस्व तथा कृषि उन्नति सम्बन्धी कार्यों के लिये दिए गये ऋण की वसूली की जा रही है। इस प्रकार की सभी वसूलियां तत्काल बन्द होनी चाहियें।

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज के अन्तर्गत गोमती नदी के "पिलकिछ घाट" पर राजमार्ग न० 105 के क्रासिंग पर एक पुल का

निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। अधिशासी अभियंता अस्थायी खण्ड जौनपुर ने मुझे सूचित किया है कि उपरोक्त पुल स्वीकृत हो गया है, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पुल का निर्माण कार्यो अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसी तरह मछली शहर के महाराजगंज तथा सुजानगंज ब्लाक के अन्तर्गत सई नदी के बेलवाघाट पर एक पुल का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। क्षेत्रीय जनता इस पुल की मांग कर रही है।

अत: सरकार से यह अनुरोध है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय महत्व के कार्यों को यथाशीघ्र करवाने के लिये तत्काल निर्देश दें।

———

14.35 hrs.

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : The House will take up the Merchant Shipping (Amendment Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z.A. ANSARI) : On behalf of my colleague, Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy, I beg to move :

That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, be taken into consideration:-

Enacting Formula

(1) That at page 1, line I, *for* the word Thirty-third, the word 'Thirty-fourth be substituted".

"*Clause I*

(2) That at page 1, line 4, *for* the figure 1982 the figure ,1983' be *substituted*".

These are technical amendments which I am presenting.

MR. CHAIRMAN : The question is:-

'That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, be taken into consideration:-

"*Enacting Formula*

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Thirty-third' the word Thirty-fourth' be *substituted*.

"*Clause 1*

(2) That at page 1 line 4, *for* the figure '1982' the figure '1983' be *substituted*".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we shall take up the amendment made by Rajya Sabha.

The question is :

Enacting Formula

"That at page 1, line 1. *for* the word Thirty-third' the word 'Thirty-fourth' be *substituted*."

"*Clause 1*

(2) 'That at page 1, line 4, *for* the figure '1982' the figure '1983' be *substituted*.

The Motions was adopted.

SHRI Z.A. ANSARI : I beg to move :— 'That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to.'

MR. CHAIRMAN : The qestion is :

'That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agree to.'

The Motion was adopted.

———

14.40 hrs.

MOTION *RE* TWENTY-NINTH, THIRTIETH AND THIRTY-FIRST REPORTS OF U.P.S.C.

MR. CHAIRMAN : The house will now take up further consideration of the following motion moved by Shri P. Venkatasubbaiah on 5th November, 1982, namely :—